







Which state has topped in implementation of 'Amrit Sarovar program'? Q.1 'अमृत सरोवर कार्यक्रम' के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? Likephone

Milmo









- With the construction of 8,462 Amrit Sarovars (lakes). Uttar Pradesh has topped the states in the implementation of Amrit Sarovar Mission, which aims at conserving water for the future.
 Madhya Pradesh is ranked second, Jammu and Kashmir third,
 Rajasthan fourth and Tamil Nadu fifth in the implementation of Mission Amrit Sarovar.
 - 8,462 अमृत सरोवरों (झीलों) के निर्माण के साथ, उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर मिशन के कार्यान्वयन में राज्यों में शीर्ष पर है, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है।
 - मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे, जम्मू-कश्मीर तीसरे, राजस्थान चौथे और तमिलनाडु पांचवें स्थान पर है।





Q.2 Which Ministry is associated with GEF Small Grants Programme'? कौन सा मंत्रालय 'जीईएफ लघु अनुदान कार्यक्रम' से जुड़ा है?

> GIEF - Glabal Emir Jacility

[A] Ministry of MSME

[B] Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Ellnigm

[C] Ministry of Finance

[D] Ministry of Corporate Affairs



GS/ GK का महासंग्राम



- •/Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme' is jointly implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the United Nations Development Programme and The Energy and Resources Institute (TERI). UN DP It provides financial and technical support to projects that restore environment while enhancing lives of local communities. The project aims to work on biodiversity, climate change and land degradation through funding of NGOs. • 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) लघु अनुदान कार्यक्रम' पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
 - यह उन परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो स्थानीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाते हुए पर्यावरण को बहाल करते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण के माध्यम से जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण पर काम करना है।







Q.3 Which state implements the 'SRESTHA-G' Programme? कौन सा राज्य 'श्रेष्ठ-जी' कार्यक्रम लागू करता है?











The World Bank has approved a USD 350 million loan to Gujarat for spending towards public healthcare services, focussed specially on adolescent girls and disease surveillance.

adolescent girls and disease surveillance.
A. The funding from World Bank arm International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), will be utilised through the state government's Systems Reform Endeavours For Transformed Health Achievement In Gujarat (SRESTHA-G) Programme.

 विश्व बैंक ने विशेष रूप से किशोर लड़कियों और रोग निगरानी पर केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए गुजरात को 350 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है।

 विश्व बैंक की शाखा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) की फंडिंग का उपयोग राज्य सरकार के सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात (एसआरईएसटीएचए-जी) कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा।





Jan Awrogya



Like/Shore

[A] NRHM and NUHM

[B] AB PM-JAY and ABDM

Yojna

C] PMSSY

D] SUMAN

Q. 4 Arogya Manthan' Event was held to mark the anniversaries of which schemes? 'आरोग्य मंथन' कार्यक्रम किस योजना की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था?

mord

Fednique



GS/ GK का महासंग्राम



- To mark the anniversaries of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan
 Arogya Yojana (AB PM-JAY) and Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) the National Health Authority organized 'Arogya Manthan'.
- Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya awarded best performing states for PMJAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) and ABDM (Ayushman Bharat Digital Health Mission).
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 'आरोग्य मंथन' का आयोजन किया।
 - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने PMJAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) और ABDM (आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन) के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया।







Q.5 Which Union Ministry launched the 'Green Energy Open Access Portal'? किस केंद्रीय मंत्रालय ने 'ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल' लॉन्च किया?

Kupwond Technique



[A] Ministry of Power
[B] Ministry of Rural Development
[C] Ministry of Environment, Forest and Climate Change
[D] Ministry of Home Affairs







• The Union Minister of Power and New and Renewable Energy, R K Singh launched the Green Energy Open Access Portal.



It aims to ensure affordable, sustainable, and green energy for all and continuation of several green initiatives. Any consumer with a connected load of 100 kW or above can get Renewable Energy through open access and the application for open access can be made on this portal.
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया।

 इसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना और कई हरित पहलों को जारी रखना है। 100 किलोवाट या उससे अधिक कनेक्टेड लोड वाला कोई भी उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और ओपन एक्सेस के लिए इस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।







Q.6 Which state launched the 'Mission Basundhara 2.0' scheme? किस राज्य ने 'मिशन बसुंधरा 2.0' योजना शुरू की?











• Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma launched the Mission Basundhara 2.0 initiative, after the success of Mission Basundara.

- The Chief Minister also launched the National Generic Documents Registration System (NGDRS) and e-stamping facilities in the State. The services under Mission Basundhara 2.0 are ownership rights to occupancy tenants, settlement of transferred annual Patta land among others.
- मिशन बसुंदरा की सफलता के बाद असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने मिशन बसुंधरा 2.0 पहल शुरू की।
 - मुख्यमंत्री ने राज्य में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) और ई-स्टांपिंग सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत सेवाओं में किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार, हस्तांतरित वार्षिक पट्टा भूमि का निपटान और अन्य शामिल हैं।















- Union Education Ministry has recently signed MoU with FIFA and AIFF for implementing 'Football4Schools' initiative in India.
- 'Football4Schools' program is expected to be a positive tool to inspire children and ensure their holistic development, by main-streaming sports along with studies.
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारत में 'फुटबॉल4स्कूल' पहल को लागू करने के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- उम्मीद है कि 'फुटबॉल4स्कूल' कार्यक्रम बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को मुख्य धारा में शामिल करके प्रेरित करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने का एक सकारात्मक उपकरण होगा।







Q.8 Which state launched 'Ladli Laxmi 2.0 financial assistance scheme'? किस राज्य ने 'लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना' शुरू की?











- Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan launched the state government's flagship 'Ladli Laxmi 2.0' financial assistance scheme.
 - The scheme aims to encourage girls to pursue higher education and make them independent. The state had launched the 'Ladli Laxmi' scheme in 2007, to provide monetary benefits to the eligible girl children to ensure they get good education.
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की प्रमुख 'लाडली लक्ष्मी 2.0' वित्तीय सहायता योजना शुरू की।
 - इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वतंत्र बनाना है। राज्य ने पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए 2007 में 'लाडली लक्ष्मी' योजना शुरू की थी।







Q.9 Which state implemented the 'Shri Dhanwantri Generic Medical Store Scheme'? किस राज्य ने 'श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना' लागू की?











- The Chhattisgarh government launched the 'Shri Dhanwantri Generic Medical Store Scheme' in October 2021.
 - It provides medicines at affordable rates to people based on the below-the-poverty line card, and is being implemented by the urban development department. Discounts of 50-70 per cent are offered on medicines, life-saving and expensive drugs and medical equipment.
 - छत्तीसँगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2021 में 'श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना' शुरू की।
 - यह गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड के आधार पर लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं प्रदान करता है, और इसे शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दवाओं, जीवन रक्षक और महंगी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर 50-70 प्रतिशत की छूट दी जाती है।







Q.10 Which Union Ministry has notified the 'National Bioenergy Programme'? किस केंद्रीय मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम' को अधिसूचित किया है?



[A] Ministry of New and Renewable Energy
[B] Ministry of Power
[C] Ministry of Commerce and Industry
[D] Ministry of MSME

Lilustore ...



GS/ GK का महासंग्राम



 The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India has notified the National Bioenergy Programme.

• The Ministry has continued the National Bio-energy Programme for the period from FY 2021-22 to 2025-26. The Programme has been recommended for implementation in two phases and the Phase-I of the Programme has been approved with a budget outlay of Rs. 858 crore. It consists of three subschemes: Waste to Energy Programme, Biomass Programme and Biogas Programme.

- भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है।
- मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखा है। कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए अनुशंसित किया गया है और कार्यक्रम के चरण- I को 858 करोड़. रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इसमें तीन उप-योजनाएँ शामिल हैं: अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम।







Q.11 What is the name of the paperless airport entry facility launched by the Civil aviation ministry?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पेपरलेस हवाईअड्डा प्रवेश सुविधा का नाम क्या है?













- The Digi Yatra paperless airport entry facility is now functional at three airports in the country, including Delhi's Indira Gandhi International, Bengaluru and Varanasi airports.
- Based on the Facial Recognition Technology (FRT), Digi Yatra aims to achieve seamless and contactless processing of passengers at airports. By March 2023, four more cities will be added: Hyderabad, Kolkata, Pune, and Vijayawada.
- डिजी यात्रा पेपरलेस हवाई अड्डा प्रवेश सुविधा अब देश के तीन हवाई अड्डों पर कार्यात्मक है, जिसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई 16 अड्डे शामिल हैं।
- अड्डे शामिल हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) पर आधारित, डिजी यात्रा का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की निर्बाध और संपर्क रहित प्रक्रिया प्राप्त करना है। मार्च 2023 तक, चार और शहर जोड़े जाएंगे: हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा।







Q.12 Which institution implements the 'Community Innovator Fellowship' programme? कौन सी संस्था 'कम्युनिटी इनोवेटर फ़ेलोशिप' कार्यक्रम लागू करती है?







GS/ GK का महासंग्राम



- Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog announced the launch of applications for Community Innovator Fellowship (CIF).
- It is an initiative of Atal Innovation Mission, NITI Aayog in collaboration with UNDP India to facilitate knowledge building and provide infrastructure support to aspiring community innovators. At present, there are 22 community innovator fellows, who are being incubated.
- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की।
 यह ज्ञान निर्माण की सुविधा प्रदान करने और इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग की एक पहल है। वर्तमान में, 22 कम्युनिटी इनोवेटर फेलो हैं, जिनका इनक्यूबेशन किया जा रहा है।







Q.13 What is the interest subvention rate provided under the 'Ethanol interest subvention scheme'?

'इथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजना' के तहत प्रदान की जाने वाली ब्याज सबवेंशन दर क्या है?



[A] 2 per cent per annum
[B] 4 per cent per annum
[C] 6 per cent per annum
[D] 8 per cent per annum







- The Government has given in-principle approval to nine more ethanol projects under its ethanol interest subvention scheme.
- The projects are expected to add to the additional capacity of about 35 crore litres. The government is extending financial assistance in the form of interest subvention at 6 per cent per annum or 50 per cent of the rate of interest charged by banks, whichever is lower, on the loans to be extended by banks for five years.
- सरकार ने अपनी इथेनॉल ब्याज सहायता योजना के तहत नौ और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- इन परियोजनाओं से लगभग 35 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। सरकार बैंकों द्वारा पांच साल के लिए दिए जाने वाले ऋण पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, ब्याज छूट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।







Q.14 'National Health Authority's Scan and Share Service' was launched as part of which scheme?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा' किस योजना के भाग के रूप में शुरू की गई थी?



[A] Swachh Bharat Mission
[B] Ayushman Bharat Digital Mission
[C] Mission Indradhanush
[D] Janani Suraksha Yojana







- National Health Authority's Scan and Share service has been adopted by 365 hospitals across 25 states and UTs in India within five months of its launch.
- It was launched as part of Ayushman Bharat Digital Mission. The service enables paperless and instant token generation for outpatient department (OPD) registration using a unique QR code displayed by participating hospitals.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा को इसके लॉन्च के पांच महीनों के भीतर भारत के 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 365 अस्पतालों द्वारा अपनाया गया है।
- इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह सेवा भाग लेने वाले अस्पतालों द्वारा प्रदर्शित एक अद्वितीय क्यूआर कोड का उपयोग करके बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) पंजीकरण के लिए कागज रहित और तत्काल टोकन पीढ़ी को सक्षम बनाती है।







Q.15 Who are the beneficiaries of the 'Sagar Parikrama' programme? 'सागर परिक्रमा' कार्यक्रम के लाभार्थी कौन हैं?



[A] Defence personnel
[B] Fishermen
[C] Non-Resident Indians
[D] Exporters







- Sagar Parikrama Phase IV was launched recently. The main objective of 'Sagar Parikrama' is to facilitate interaction with fishermen, coastal communities and stakeholders to disseminate information of various fisheries related schemes and programs.
- It also aims to promote responsible fisheries and protection of marine ecosystem.
- सागर परिक्रमा चरण IV हाल ही में लॉन्च किया गया था। 'सागर परिक्रमा' का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करने के लिए मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना भी है।







Q.16 Which Union Ministry has organised Swachhotsav 2023 campaign? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव 2023 अभियान का आयोजन किया है?



[A] Ministry of Housing and Urban Affairs
[B] Ministry of Home Affairs
[C] Ministry of Rural Development
[D] Ministry of Agriculture and Farmers Welfare







- As part of the ongoing Swachhotsav 2023 campaign, the Mission is set to mobilize citizens from over 2,800 cities as part of the 'Swachh Mashaal March'.
- The Mashaal March aims to spread awareness regarding the idea of a 'Garbage Free City'. It is organised by Ministry of Housing and Urban Affairs.
- चल रहे स्वच्छोत्सव 2023 अभियान के हिस्से के रूप में, मिशन 'स्वच्छ मशाल मार्च' के हिस्से के रूप में 2,800 से अधिक शहरों के नागरिकों को जुटाने के लिए तैयार है।
 मशाल मार्च का उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहर' के विचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।